

राज्य सूचना आयोग

RAJASTHAN POLITY

BY – NITESH SIR

SECTIONS

PHYSICS	CHEMISTRY
BIOLOGY	HISTORY
POLITICAL SCIENCE	GEOGRAPHY
ECONOMICS	COMPUTER
ENGLISH	MATHEMATICS
HINDI	STATIC GK
STATE PCS	QUIZZES

TEST SERIES

CURRENT AFFAIRS

INTERESTING FACTS

BRAIN TEASER

कवि और कहानीकार

TELEGRAM GROUP LINK 1

[CLICK HERE](#)

TELEGRAM GROUP LINK 2

[CLICK HERE](#)

YOUTUBE CHANNEL

[CLICK HERE](#)

WHATSAPP GROUP LINK

[CLICK HERE](#)

राज्य सूचना आयोग

प्रथम देश जहाँ सूचना का अधिकार कानून लाया गया - स्वीडन (1765 ई)

भारत का प्रथम राज्य जहाँ RTI कानून लाया गया - तमिलनाडु (1996 ई)

राजस्थान में सूचना का अधिकार - 2008 ई (क्रियान्वयन 26 जनवरी 2001)

सूचना के अधिकार कानून हेतु सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय - SP गुप्ता बनाम भारत सरकार (1982 ई)

महत्वपूर्ण संगठन जिन्होंने सूचना के अधिकार हेतु प्रयास -

मजदूर किसान शक्ति संगठन - श्रीमती अरुणा रॉय

परिवर्तन - श्री भरविंद चैपरीवाल

NITESH SIR NOTES

राजस्थान का राज्य सूचना आयोग -

यह एक संबिधित आयोग है, क्योंकि इसकी स्थापना सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 18 के अंतर्गत की गई है।

आयोग की स्थापना की अधिसूचना जारी - 13 अप्रैल 2006

आयोग की स्थापना - 18 अप्रैल 2006

प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त - श्री MD कोरानी

आयोग की संरचना -

1 मुख्य सूचना आयुक्त व 10 राज्य सूचना आयुक्त के राजस्थान राज्यस्थान में 1+4

→ मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता ।

श्री राजेंद्र प्रसाद बरबड़
श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़
शील धनरथ
श्री ML लाखड़ (पूर्व DGP)

योग्यता -

NITESH SIR NOTES

लोक सेवक न्यायिक अधिकारी
शिवा विन पत्रकार
समाज सेवक

इसलिए जो मुख्य सूचना प्राप्त या राज्य सूचना प्राप्त निपुण क्रिया जा सकता है।

निपुण -

राज्यपाल द्वारा एक समिति की शिफारिश पर - मुख्यमंत्री
विधानसभा में विपक्ष का नेता
CG द्वारा मनोनीत केबिनेट मंत्री

क्षेत्र -

राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति / राज्यपाल

कार्यकाल -

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारण (RTI Act 2019 द्वारा)
वर्तमान में - 3/65 वर्ष जो भी पहले हो।

स्तीका -

राज्यपाल को स्तीका।

वेतन अने -

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित (2019 से)
राज्य सूचना प्राप्त - उच्च न्यायालय के (HC)
न्यायाधीश के समान।

मुख्य सूचना प्राप्त - उच्च न्यायालय के CG के
समान

निष्कासन -

कदाचार व असमर्थता के मामले में राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात।
राज्यपाल द्वारा सीधा व प्रत्यक्ष रूप से - दिवंगतिपान

लाभ का पद
नैतिक पतन
मानसिक विकृति

NITESH SIR NOTES

वार्षिक प्रतिवेदन -

राज्य सरकार को सौंपता है।

आयोग को 250 से 25 हजार तक रु का जुमाना लगाना का अधिकार है।

सूचना का अधिकार कानून 2005 की महत्वपूर्ण धाराएँ -

धारा	प्रावधान
6 (1)	अपील का प्रारूप
15	राज्य सूचना आयोग का प्रावधान, संरचना
16	कार्यकाल
17	निष्कासन
18, 19, 20, 23	आयोग के कार्य
19	अपील की प्रक्रिया
19(1)	प्रथम अपील अधिकारी
19(3)	द्वितीय अपील अधिकारी (राज्य सूचना आयोग)
19(7)	आयोग के आदेशों का अन्वयकारी होगा
19(8)	आयोग द्वारा लोक प्राचीकरणों या सस्यवाचकों का पर्यवेक्षण

NITESH SIR NOTES

राज्य सूचना आयोग

RAJASTHAN POLITY

BY – NITESH SIR

SECTIONS

PHYSICS	CHEMISTRY
BIOLOGY	HISTORY
POLITICAL SCIENCE	GEOGRAPHY
ECONOMICS	COMPUTER
ENGLISH	MATHEMATICS
HINDI	STATIC GK
STATE PCS	QUIZZES

TEST SERIES

CURRENT AFFAIRS

INTERESTING FACTS

BRAIN TEASER

कवि और कहानीकार

TELEGRAM GROUP LINK 1

[CLICK HERE](#)

TELEGRAM GROUP LINK 2

[CLICK HERE](#)

YOUTUBE CHANNEL

[CLICK HERE](#)

WHATSAPP GROUP LINK

[CLICK HERE](#)